dry farming and water management practices. The State Government also proposes to provide cash doles to 2 lakh indigent persons who cannot be covered under the Relief works programme. The State Government has also re-scheduled the short-term co-operative loans and waived the interest liability in respect of short-term loans given to small and marginal farmers in the drought affected areas. At the request of the State Government a Central Team visited Gujarat from the 19th to the 21st May, 1980 for an on-the-spot assessment of the drought situation and recommending Central assistance . The State Government has been allocated 10,000 MT foodgrains under the Food for Work Programme in April, 1980. On the basis of the report of the Team, Central assistance will be released very shortly. Government of India have already allocated short-term loan of Rs. 4 crores for purchase and distribution of agricultural inputs during Kharif season.

Payment of Salary to Teachers of K.S.D. Sanskrit University

93. SHRI HARINATH MISHRA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that K.S.D. Sanskrit University, Bihar, is a recognised institution by the U.G.C.;

(b) whether teachers of Sanskrit colleges and Vidyalayas affiliated to the University are either not receiving their salary according to norms prescribed by the State Government, or receiving no emoluments at all; and

(c) if so, the number of teachers involved and the steps that have been taken or are proposed to be taken to remove their grievances?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). As the Sanskrit Colleges affiliated to, and the Vidyalayas recognised by, the KSD Sanskrit University receive financial assistance from the Government of Bihar, the State Government has been requested to look into the matter.

चीनी के कारखाना मूल्य कम करने के लिए चीनी मिल मालिकों को निदेश

94. **श्री कमल मिश्र मधुकर:**
श्री ओस्कर फर्नाण्डीस :
श्री के. प्रधानी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने सभी चीनी मिल मालिकों को निदेश जारी किये हैं अथवा कोई अपील की है कि वे स्वेच्छा से चीनी के कारखाना मूल्य कम करें ;

(ख) यदि हां, तो कितने चीनी मिल मालिकों ने इस निदेश का पालन किया है और कितने चीनी मिल मालिकों ने इसका पालन नहीं किया है;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के पूर्व चम्पारन जिले के बाराचकियां और मोतीहारी शुगर मिल द्वारा सरकार के इस निदेश का पालन किया गया था ;

(घ) क्या सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि यदि चीनी मिल मालिकों द्वारा इस निदेश का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कडी कार्यवाही की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) से (ङ): सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी नहीं किया है क्योंकि चीनी की मौजूदा दोहरी मूल्य प्रणाली जिसमें केवल लेवी चीनी का सांविधिक मूल्य निर्धारित किया जाता है, के अधीन ऐसा निदेश करने का विचार नहीं है और इसलिए इस संबंध में व्यक्तिगत मिलों की प्रतिक्रिया को निगरानी करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, सरकार सामान्यतया खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों पर निगरानी रख रही है और जब वे अनुचित रूप से ऊंचे स्तर तक पहुंच जाते हैं तब